

संपादक की कलम से

आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र को नयी सरकार से उम्मीदें

नरेंद्र मोदी के 2014, 2019 और अब 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास के मौर्चे पर और बेहतरी आने की उम्मीदें हैं। क्योंकि 2014 और 2019 की अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सेवा आदि क्षेत्रों को विकसित करने एवं सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इस क्रम में सबसे कारगर और समर्पित कदम आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में उठाये गये हैं। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान भारत आर्थिक रूप से विश्व में एक मजबूत देश बनकर उभरा है। इसलिए, देशवासियों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत 2027 में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2030 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में विकसित देश बन सकता

वर्ष 1947 से ठीक 60 वर्षों के बाद भारत की जीडीपी 2007 में एक ट्रिलियन डॉलर की हुई और 2014 में दो ट्रिलियन डॉलर की हो गयी तथा 2019 में तीन ट्रिलियन डॉलर की। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी थी, जबकि 2019 में यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी। वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से जीडीपी में वृद्धि दर्ज हुई और समग्र रूप से वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 8.2 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह सात प्रतिशत रही। हाद इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत की जीडीपी बढ़ि दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है। वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही थी, जबकि 2022 में 7.3 प्रतिशत। चूंकि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसलिए, 2024 से 2027 तक बेरोजगारी दर के आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारत में मुद्रास्फीति दर 2023 में 5.5 प्रतिशत रही है, जबकि 2022 में यह 6.7 प्रतिशत रही थी। मई 2024 में खुदरा महानाई 4.75 प्रतिशत रही, जो 12 महीने का निचला स्तर था। वर्ष 2024 से 2027 के दौरान इसके क्रमशः 4.6, 4.1, 4.1 और 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस आधार पर कहा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आसानी से 2027 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की बन सकती है। हाद इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा किये जा रहे अर्थिक सुधारों के चलते ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकी है। इस रिपोर्ट में यह संभावना भी जतायी गयी है कि भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एंजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आयी मजबूती और सरकार द्वारा किये गये हालिया संरचनात्मक सुधारों के कारण इस दावे की पुष्टि की है। एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट हान्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक्हल में कहा है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जायेगी।

हाल के महाना में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। देश के तीन बड़े बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक- ने 2023 में दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनायी है। एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय स्थिति में सुधार, मजबूत आर्थिक स्थिति, कर्ज में तेज वृद्धि, एनपीए में कमी और मुनाफे में इजाफे से भारतीय बैंक मजबूत हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.5 प्रतिशत बढ़कर 1.51 लाख करोड़ डॉलर हो गयी है। हाल के महीनों में भारतीय बैंकों द्वारा दिये जा रहे कर्ज में तेज वृद्धि हुई है। उनतीस दिसंबर, 2023 तक यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी थी, जो एक वर्ष पहले 14.9 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने 10,000 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने तो इस अवधि में 61,077 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो सरकारी बैंकों की कुल कमाई के 40 प्रतिशत से अधिक है। बारह सरकारी बैंकों में से केवल पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे में कमी आयी है। इकतीस मार्च, 2024 को सरकारी बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में सभी बैंकों का एनपीए भी घटकर 1.70 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ गया।

विकासत दश बनन कुछ मानक है। इस क्रम म भारत म आद्यागाकरण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, यंत्रीकरण, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। लोगों की जीवन प्रत्याख्या और शिक्षा में सुधार आ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, सेल्फ हेल्प युप आदि की मदद से देश में समावेशी विकास को बल मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। विगत वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। इस तरह, प्रति वर्षीय आय के मानदंड को छोड़कर भारत अन्य मानकों पर खरा उत्तरकर विकसित देश की श्रेणी में जरूर खड़ा हो सकता है। (ये लेखक के निजी विचार हैं।)

स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान

ऑनलाइन हेल्प इंश्योरेंसः फायदे, सावधानियां और भारत में बेस्ट प्लान्स देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बेहतर करने के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के आकलन के लिए एक वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की स्थापना, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर में सुधार एवं निगरानी के लिए नया डैशबोर्ड तथा खाद्य पदार्थ बेचने वाले वेंडरों के लिए त्वरित लाइसेंस और पंजीकरण की व्यवस्था इन पहलों में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार 1.73 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित कर चुकी है। एम्स संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में

हाल के वर्ष में उत्साहजनक बढ़ातरा हुई हैं। साथ ही, जन आधारिकद्रा के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण दिवाइया उन्नित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। ऐसे प्रायोगिकों के लाभ सही ढंग से लोगों को मिलें, इसके लिए निगरानी और आकलन की व्यवस्था आवश्यक है।

डिजिटल तकनीक पर आधारित होने से यह व्यवस्था पारदर्शी भी होनी तथा इसमें समय एवं अन्य संसाधनों का व्यय भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर पूरी आवादी को उपलब्ध हों। इस संबंध में आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, बीमा सुविधा आदि के विस्तार से उम्मीदें बंधी हैं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। हाल में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया है। इसमें स्वास्थ्य केंद्रों में इंफास्ट्रक्चर, डॉक्टरों एवं

नसों की उपलब्धता, साजो-सामान की स्थिति अपार्दि के बारे में जानकारी जुटायी गयी है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 80 प्रतिशत केंद्र निर्धारित मानकों एवं स्तरों पर खरे नहीं उत्तर हैं। सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है, उसमें एक यह भी है कि 70 हजार स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर के अनुरूप बनाया जायेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रस्तावित डैशबोर्ड बहुत सहायक होगा। भारत में दो लाख से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, जिनमें जिला अस्पताल, प्राथमिक प्राकाशन और अपार्दि अस्पताल आगे एवं पर्याप्त संख्या उपलब्ध हैं।

बरसात के पानी का पोल - खोल अभियान

@ राकेश अचल

बरसात इंडी और सीबीआई से ज्यादा मजबूत जांच एजेंसी है। बरसात का पानी देश में समानदृष्टि से निर्माण कार्यों में हुई धांधली की पोल खोलता है। बरसात का पानी जो भी करता है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करता है। बरसात का न किसी गंठबंधन के साथ तालमेल है और न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बरसात तो आती है और अपना काम कर वापस लौट जाती है दोबारा आने के लिए। इस बरसात ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की पोल खोली है। बरसात का ये पोल-खोल अधियान अभी जारी है। देश में बरसात कमोवेश हरेक हिस्से में होती है। कहीं कम, तो कहीं ज्यादा। बरसात को अपना काम करने के लिए न जनादेश की जरूरत पड़ती है और न किसी अध्यादेश की। बरसात का नियंता तो इंद्र है। इंद्र देवत है। खुश भी करता है और कुपित भी होता है। जब संयम से बरसाता है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि बरसात के पानी से ही खेत सोना उगलते हैं और जब कुपित होता है तो जल-प्लावन कर असंख्य जानें ले लेता है। इस लिहाज से बरसात का, बादलों का नियंता बहुरूपिया है हमारे नेताओं की तरह। इंद्र की फिरत रसैकड़ों, हजारों सालों से नहीं बदली। देश-दुनिया में सरकारें बदलती हैं किन्तु इंद्र नहीं बदलता। द्वारा में इंद्र का मान-मर्दन करने के लिए कृष्ण थे। उन्होंने गोवर्धन को अपनी लाठी पर ऊपर उठाकर बचा लिया था, लेकिन कलियुग में इंद्र तो है किन्तु कोई कृष्ण नहीं है। नेता, इंजीनियर और ठेकेदार खबर कमाते-खाते हैं लेकिन इन सबकी पोल बरसात के जरिये इंद्र ही खोलते हैं। इस बार सबसे पहले विहार की पोल खुली। एक के बाद एक कर कोई एकदर्जन पुल गिर गए। किसी का कुछ नहीं बिंगड़ा। कुछेक इंजीनियर निलंबित किये गए। उन्हें बरसात के बाद बहाल कर दिया जाएगा। जो पुल बहे वे बदनसीब थे। सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार का काम पुल बनाना है और बरसात का काम पुल गिराना और बहाना है। यदि पुल बहेंगे नहीं तो नए कहाँ से बनेंगे। आज के नेता शेरशाह सूरी या कोई अंग्रेज तो नहीं हैं जो ऐसे पुल बनवा दें जो सदियों तक चलें? हमारे देश में मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के तमाम पुल अभी भी पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं।

देश में बहने या गिरने का काम केवल पुल ही नहीं करते, हवाई अड्डे की छतें और केनोपी भी करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरागंधी हवाई अड्डे की केनोपी टपक रही हैं। कर पार्किंग की छत बैठ गयी है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और अयोध्या में बनाये गए नए-नवेले हवाई अड्डे निर्माण कार्यों की पोल खोल रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की तिवारें ही नहीं रामलला के नवनिर्मित मर्दिंग की छत भी टपक रही है। लेकिन किसी का न तो रोम फड़क तरह है और न कोई इस बारे में सोच रहा है।

सरकार का बस चले तो वो इस तरह का पोल-खोल अधियान चलने वाले इंद्र को स्वर्ग से

www.english-test.net

A white truck is stuck in floodwaters, its front end submerged. Several people with umbrellas are gathered around it, some appearing to be trying to help or assess the situation. The water is brown and turbulent. In the background, there's lush green vegetation and a few other vehicles, including a blue tricycle-like vehicle.

गिरफ्तार कर हवालात में डाल दे, लेकिन ये हो नहीं सकता। कोई ईडी या सीबीआई वाला स्वगारौहण कर इन्द्र की गिरफ्तारी करने का करिश्मा नहीं दिखा सकता। बैशाखियों पर टिकी सरकार के पास भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वो इन्द्र को हटक सके। बरसात को होने से रोक सके। सरकारें अपना काम कर रहीं हैं और बरसात अपना काम कर रही है। सरकार बरसात से नहीं डरती और बरसात सरकार से नहीं डरती। असम से अयोध्या तक, दिल्ली से पटना तक देश के किसी भी हिस्से में जाइये, आपको बरसात सरकार के निर्माण कार्यों की पोल खुलती दिखाई देगी। पुल ही नहीं सड़कें भी सरकार की पोल खोलती हैं। बरसात में नदीं ही नाले भी उफन कर दिखा देते हैं। लेकिन सरकार न नदी का कुछ बिगाड़ सकती है और न नालों का। पाना बरसाने वाल बादलों के खिलाफ तो कुछ कर पाना मुमिन ही नहीं हैं केंद्र की सरकार 23 जुलाई से बरसात की परवाह किये बिना ही केंद्रीय बजट ला रही है। ये सीतारामी बजट होता है। देश के पास श्रीमती निर्मला सीतारामन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वे लगातार चमकार करती आ रहीं हैं इसलिए उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। बजट के मामले में निर्मला जी का स्मार्थन उनके अपने पति देव भी नहीं करते ऐसे में जनता उनके बजट का समर्थन क्यों करने लगी ? एक जमाना था जब मुगल हों अंग्रेज हों या देशी राजे-महाराजे हों कम से कम निर्माण कार्यों में तो कर्माई नहीं करते थे। घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते थे, यदि करते होते तो ग्वालियर के पास नूराबाद में शेरशाह सूरी के जमाने का बना पुल, कोलकता में हुबली पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल और तो और छोड़ि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम बदनाम हो चुके सिंधिया खाननवांद्वारा बनाये गए पुल और बाज भी काम कर रहे हैं। पिछे 75 साल में बनाया गया कोई पुल और सड़क पुराने जमाने निर्माण कार्य का मुकाबला न कर सकता। जाहिर है कि तब और अब में बहुत अंतर आ चु है। इमानदारी का इंडेक्स लगातार गिरा है। पिछले दस सालों में तो इस इंडेक्स में इतनी गिरावट है की पूछिए मत ! आप पूछें भी तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ असीमित है। बरसात देश और दुनिया असंख्य लोगों को प्रभावित करती है। भारत में भी यही हाल असम के 30 जिलों के लाखों लोग राहत शिविरों में हैं। चारधारी यात्रा स्थगित कर दी गयी

दिल्ली जलमग्न है। अयोध्या हो या काशी सब जगह पानी ही पानी है सिवाय सरकारों और नेताओं की आखों के। सरकारें देखकर भी कुछ देखना नहीं चाहतीं और नेताओं को पानी हवाई जहाज में बैठकर देखने में मजा आता है। वे हवाई सर्वे करते हैं फिर राहत बाट-बटवाते हैं। राहत कार्य भी निर्माण कार्यों की तरह कमाई का एक दूसरा जरिया होते हैं। टीडीपी और जेडीयू तो इस बार सरकार का हिस्सा बनकर उसे निचोड़ लेने पर आमादा हैं, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा ? इस साल में पहली मरतबा भाजपा लंगड़ी-लूलू हुई है। इसलिए सब मिलजुलकर अपना-अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

इस बार यानास काहव वा मनसून सीजन कहिये में अभी तक केवल और केवल पानी से लड़े काले बादल ही गुरुगुराते दिखाई दिए हैं। इन्द्रधनुष तो दिखाई ही नहीं दिया कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है बरसात न आये तो आलूप्याज और टमाटरों को अपने भाव बढ़ाने का मौका ही कहाँ मिले? बरसात सबका खाल रखती है। जमाखोरों का भी, जो इस मौसम में मुनाफा नहीं कमा पाटा उसके लिए कोट दूसरा मुफीद मौसम होता ही नहीं है। मुझे तो बरसात का मौसम बेहतु सुहाना लगता है। मन बाग-बाग हो जाता है। आपकी आप जानें। मुझे तो बरसात ईडी और सीबीआई से भी ज्यादा भरोसे की लगती है, कम से कम समय पर पोल तो खोलती है। आइये बरसात का इंद्र का अभिनंदन करें। पकड़े तलने के राष्ट्रहितीयी अभियान में प्राण-पन से जुट जाएँ।

ਬੋਨਿਫਿਟਾ ਆਫ ਰੇਨ

शिफाई कुछ यूं लिखते हैं - 'दूर तक छाए थे बादल और कहीं सायान
न था इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था'। आजकल संपूर्ण
भारत में जगह जगह खूब बारिश हो रही है। आदमी पहले गर्मी से
परेशान था, आजकल बारिश से। पहले लोग बारिश आने के लिए यज्ञ
और हवन करते हैं और बाद में बारिश रोकने के लिए। बड़ा झंझट है
बारिश का। बारिश आती है तो लोग घरों के अंदर घुसते हैं और
बारिश का पानी नलियों में घुसना पसंद नहीं करता, पानी नलियों से
बाहर बिखरता है। दरअसल, बारिश का पानी पालीथीन बैग्स व कचरे
के साथ खेलता है।

अजी ! कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बारिश प्रेमी-प्रेमिका
के रोमांस का ही सीजन नहीं है। नलियों का पानी भी सड़क व गलियों
से अच्छा खासा रोमांस करता है। बारिश से नलियां, सड़कें, खड़डे
पानी से भर जाते हैं और हमारी गाड़ियां गंदी हो जाती हैं। कपड़े भी
गंदे हो जाते हैं। अजी ! बारिश के अपने फायदे हैं कि कार वाशिंग करने
वालों, लांड्री वालों व ठेकेदारों को काम मिलता है। बेरोजगारी का

नामानिशान तक नहीं बचता। वैसे बारिश का सबसे ज्यादा फायदा सड़कों व पुलों का ठेका लेने वालों को होता है। सड़कें और पुल बारिश में बह जाते हैं और ठेकेदारों को अनाप-शनाप काम पर काम मिलता है। फटाक से देश से बेरोजगारी दूर होती है। पकड़े तलने वालों को भी बारिश में अच्छा खासा काम मिल जाता है। आइसकीमप्रबन्ध बेचने वाले पकड़ा व्यवसाय की ओर पलायन करने लगते हैं। भरी गर्मी में बारिश आने से चाय और कॉफी वालों का मंद पड़ा धंधा चमकने लगता है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को बारिश में गाने फिल्माने का काम मिल जाता है। उन्हें आर्टिफिशियल बारिश का झाँझट नहीं पालना पड़ता। इतना ही नहीं अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को मेकअप को धोने का भी झाँझट नहीं करना पड़ता। बारिश में मेकअप अपने आप धुल जाता है। एक फायदा बारिश का यह भी है कि बारिश में पानी मुफ्त में मिलता है, पानी के टैंकर गिराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। साबुन और वाशिंग पाउडर इंडस्ट्री का खूब माल बिकने लगता है। बारिश में पानी के लिए मोटर भी नहीं चलानी पड़ती। आदमी को भगवान को ही अरदास करनी पड़ती है कि 'भगवान जी अब तो मोटर बंद कर दीजिए, पानी फुल हो गया है'। बारिश का एक मजा यह भी है कि आप नावों को ही नहीं करारें, मोटरसाइकिलों व अन्य साधनों को भी तैरता हुआ देख सकते हैं। वैसे बारिश का एक फायदा यह भी है कि हम सड़कों को धान रोपाई व स्वीमिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं।

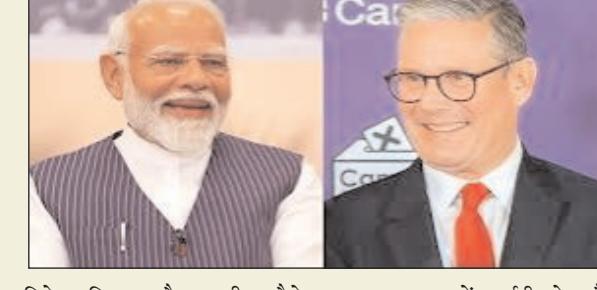
ओर तो ओर थोड़ा बहुत बारिश में केब वाले स्वयं का भगवान मान बैठते हैं। बारिश का एक आनंद यह भी है कि आपको बार-बार बाथरूम के अंदर जा कर नहाना नहीं पड़ता। बारिश का फायदा क्रिकेट मैच में भी होता है। गीली आउटफील्ड के कारण बालरों को कम ओवर करने पड़ते हैं, इससे वे थकते नहीं हैं। बहुत बार न जीतने वाली टीम भी बारिश के कारण जीत जाती है। अधिक बारिश से स्कूलों में बच्चों की छुटियां भी हो जाती हैं। बारिश के कारण 'लू' लापता होता है जाती है तो इधर छाते व रेनकोट बेचने वालों की मौसमी बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे शहर में भी इन दिनों गर्मी राहत कैंप लगा हुआ है, व्यंग्य लिखने से आजकल काम नहीं चल रहा है, इसलिए बारिश के इस मौसम में हम भी पकड़े तलने जा रहे हैं। जय राम जी की

गुस्ताखी माफ।

ब्रिटेन के नए निजाम का भारत के प्रति रुख

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ब्रिटेन में 14 साल बाद लेबर

की सत्ता में शानदार वापसी हुई है। हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल सीटों में लेबर पार्टी को कुल सीटें मिली है। ऐतिहासिक जीत साथ कीर स्टाम्पर ब्रिटेन वेप्रधानमंत्री होगी। सत्ताधारी कंज पार्टी को 121 सीटें पर संतोष पड़ा है जो अब विषयक की भूमि में दिखेगी। अब सवाल यह ब्रिटेन में बदले निजाम का भारत क्या असर होगा? क्या कीर भारत को लेकर पुरानी पॉलिसी बदलाव लाएगे? फिलहाल संभावना कम है। महंगाई की तरले दबे ब्रिटेन को अपनी अस्थिरियत और फूड सप्लाइ चेन मजबूत करना शीर्ष प्राथमिकता है। ऐसे में उसके लिए भारत बहत रिश्ते बनाए रखना आवश्यक है। किसी से छिपा नहीं है कि



निकरा, याकूब और रमान की जूला व्यापक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया था। याद होगा जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जतायी थी कि दोनों देश शीशी ही प्रीटे ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को मूर्त रूप देंगे। कीर स्टार्मर के प्रधानमंत्री बनने पर भी वैसा ही रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले पर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई है। गौर करें तो सैद्धांतिक तौर पर प्रीटे ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ दोनों देशों के लिए बड़ा होगा।

ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी का निवेशकर्ता देश के रूप में उभरा है। अच्छी बात है कि आर्थिक साझेदारी को गत देवे के साथ-साथ दोनों देश स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने पर सहमति जता चुके हैं। अब यह ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर निर्भर करता है कि वह भारत के साथ आर्थिक-सामरिक रणनीतिक साझेदारी को कितना महत्व देते हैं। अगर प्रधानमंत्री कीर

एग्रीमेंट (एफटीए) की नींव पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2021 में अपनी भारत यात्रा के दौरान रखी थी। उनके बाद लिज ट्रस ने इस प्रस्तावित टेज्ड समझौते का समर्थन कर इस दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर ब्रिटेन के नए निजाम का रुख क्या होता है। फिलहाल गैर करें तो आज भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन चार लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में प्रस्तावित टेज्ड समझौता मूर्त लिया है तो निःसंदेह दोनों देशों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। मुक्त व्यापार करार के तहत व्यापार में दो भागीदार देश आपसी व्यापार वाले उत्पादों पर आयात शुल्क में अधिकतम कटौती करते हैं जिसका फायदा दोनों देशों को मिलता है। अगर प्री टेज्ड समझौते पर दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो दोनों देशों के अर्थिक भागीदारी को नई ऊँचाई मिलेगी। इससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। प्री ट्रेट्ड समझौते पर ब्रिटेन का भारत के साथ आना इसलिए भी उम्मीद जगाने वाला है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।

भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाले देश बन चुका है। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाले देश बन सकता है। एक अन्य रिपोर्ट के मताबिक अर्थव्यवस्था के आकार में थी। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत ब्रिटेन आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के साथ है। दोनों देशों द्वारा भरोसा जताया जा चुका है कि 2030 तक आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलना उनकी शोर्प्री प्राथमिकता में होगा। जहां तक द्विपक्षीय व्यापार का सवाल है तो ब्रिटेन भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार जो 2018-19 में 16.7 अरब डॉलर, 2019-20 में 15.5 अरब डॉलर था वह अब बढ़कर 40 अरब डॉलर यानी चार लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इससे दोनों देशों के तकरीबन 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। गौर करें तो ब्रिटेन में लगभग 800 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। इस संदर्भ में टाटा इंस्लैंड में नौकरियां उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी का दर्जा हासिल कर चुकी है। भारतीय कंपनियों का विदेशों में कुल निवेश 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत के बीपीओ क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का काम भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आउटसोर्सिंग दोनों देशों के लिए लाभप्रद है। एक ओर यह ब्रिटिश कंपनियों की लागत कम करता है वहीं लाखों शिक्षित भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना स्टार्म टेज्ड समझौते के साथ-साथ माइग्रेशन और मेलिलीटी पार्टनरशिप समझौते पर भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देते हैं तो निःसंदेह भारत के प्रशिक्षित लोगों को ब्रिटेन जाने की राह और आसान हो जाएगा। वैसे उम्मीद किया जाना चाहिए कि ब्रिटेन के नए निजाम में नरमी से भारतीयों को फायदा मिलना तय है। उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्म पुरानी पॉलिसी पर ही आगे बढ़ेंगे जो कंजर्वेटिव सरकार के समय थी। वैसे देखें तो कंजर्वेटिव सरकार का ज्यादा सख्त थी। उसका खामियाजा भारतीय मूल के लोगों को भुगतान पड़ा। चूंकि कीर स्टार्म चुनाव के दरम्यान इस मसले पर नरमी के संकेत दे चुके हैं ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय मूल के लोगों को इस मसले पर राहत मिलनी तय है। वैश्विक परिषेक्ष्य में देखें तो आतंकवाद से निपटने, हिंद-प्रांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दबावदारी का समर्थन, पर्यावरण, रक्षा उपकरणों व अत्याधुनिक हथियारों का साझा उत्पादन तथा अफगानिस्तान के हालात जैसे कई अन्य मसलों पर भी दोनों देशों की सोच एक जैसी है। कई वैश्विक मंचों के जरिए दोनों देश अनेकों बार अपने-अपने विचार साझा कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिटेन के नए निजाम कीर स्टार्म भारत के साथ दोस्ती को कितना परवान चढ़ाते हैं।

